आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–02 फरवरी 2026 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया वित्त वर्ष–2026–27 का केन्द्रीय बजट। कहा–आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के तीन कर्तव्यों से प्रेरित है बजट।
- बजट में दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी सहित देश के 7 हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा। वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव।
- प्रदेश भर में आम बजट का किया गया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा–145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है यह बजट।
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक की। ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग पर दिया जोर।

****

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वित्त वर्ष–2026–27 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। एक रिपोर्ट–

बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने छह सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किय है जिनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चौंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा व स्थायित्व सुनिश्चित करना और शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। बजट में प्रदेश के विकास को गति देने वाली कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट में दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी समेत देश के 7 हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया गया। साथ ही वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने सारनाथ समेत देश के 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।

केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक सात दशमलव आठ–पांच लाख करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बजट सुरक्षा–विकास–आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है।

वित्तमंत्री ने बजट में भारत को एक वैश्विक जैव–औषधि विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को शुरू करने का प्रस्ताव भी किया। बजट में आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि संशोधित या देर से रिटर्न दाखिल करने का समय 31 मार्च तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर अधिनियम– 2025, इस वर्ष अप्रैल से प्रभावी होगा। बजट में शामिल अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट–

बजट 2026–27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। कैंसर रोगियों के लिए आवश्यक 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क में छूट के साथ तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की गईहै। सरकार ने खेलों को बढावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने बजट में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भरता भारत कोष में 4 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा। हर जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये मार्ट्स की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026–27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।

भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा नई गति मिलेगी, जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वह एसपिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।

रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026–27 की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के लिए रोडमैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इस साल रेलवे को दो लाख 78 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

सात नए हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की है चेन्नई–बेंगलुरु इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा एक घंटे 13 मिनट की हो जाएगी बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे हो जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद एक घंटा 55 मिनट तो एक तरह से मुम्बई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा।

****

लोकसभा में कल पेश किये गये आम बजट का प्रदेश भर में स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है।

विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है जो बजट प्रस्तुत किया गया यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए यह नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है।

डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा। उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया।

उन्होंने जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किया है। जिसमें उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली वाराणसी अब हाई स्पीड रेल कॉरीडोर मिलेगी और वाराणसी से सिलिगुड़ी मिलेगी तो निश्चित तौर से इससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी कनेक्टिविटि बढेगी और तेज होगा और बायोफार्मा के लिए दस हजार करोड़ का प्राविजन किया है।

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने बजट का स्वागत किया। वहां के उद्यमी आर.के चौधरी ने कहा यह बजट वाराणसी के साथ पूरे पूर्वांचल के विकास को गति देगा।

बनारस में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री आएंगी, एंप्लॉयमेंट बनेगा, यह पूर्वांचल अपने आप में एक मानव संसाधन का बड़ा केंद्र है। जो लोग बाहर जाते हैं, अब उनको जाना नहीं पड़ेगा, यहां उद्योग लगेंगे। जो रेल कॉरिडोर बन रहा है, यह सब औद्योगिक विकास के द्योतक हैं।

जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने कहा कि बजट में शिक्षा, शोध, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं ने भी बजट का स्वागत किया है। आगरा की डॉ. निधि शर्मा ने बजट को ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभदायक बताया।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति' की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अन्त तक वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर अप्रूव करा ली जाए। हेड–वाइज एलोकेशन शुरुआत से ही सुनिश्चित हो और जिन मदों में आंतरिक संशोधन की आवश्यकता हो, उसे समय पर अनुमोदित कराएं, ताकि विकास कार्य बाधित न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में नई तकनीक को अपनाना चाहिए। ऐसे नए प्रयोगों को अपनाया जाए, जिनमें सड़क की कॉस्ट कम, लेकिन लाइफ ज्यादा हो। समाचार कक्ष से विवेक सिंह

उधर, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में कुल क्रेडिट डिपॉजिट –सी.डी. रेशियो को 62 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा।

****